



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 मई, 2009 / 2 ज्येष्ठ, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 मई, 2009

संख्या एच0पी0ई0आर0सी0 / सचिव-401.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 3 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्ति धारियों के निष्पादन के मानक) विनियम, 2005 में और संशोधन करने हेतु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 57 की उप धारा (1), 58 व 59 तथा धारा 86 की उप धारा (1) का खण्ड क तथा धारा 181 की उप धारा 1 तथा उप धारा 2 के खण्ड (यक) तथा (यख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने

वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, और वे एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) तथा विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचना के सूचनार्थ प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन होने की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर किसी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बावत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश, विद्युत विनियामक आयोग, क्यॉथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्ति धारियों के निष्पादन के मानक) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के निष्पादन के मानक) विनियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में :—

(क) विधान खण्ड 12 के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (13) जोड़ा जाएगा, नामतः

“(13) “कार्य—समय, घण्टे” से प्रातः 9 बजे से रात्री 9 बजे तक का कार्य समय अभिप्रेत है,” तथा

(ख) विधान खण्ड (13) को खण्ड (14) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

3. विनियम 6 में संशोधन.—उक्त विनियमों के विनियम 6 में.—

(क) आरम्भ में निम्नलिखित उप विनियम (1) और (2) अन्तः स्थापित किए जाएंगे :—

(1) केन्द्रित कॉल सेन्टर अथवा अभिहित शिकायत सेन्टर में अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय के बन्द होने, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में कमी, मीटरों, बिलों इत्यादि के बारे में उपभोक्ता की प्रत्येक शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उपभोक्ता को शिकायत रजिस्ट्रीकरण की संख्या तथा समय को सूचित करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी सभी उपभोक्ताओं के साथ उचित बर्ताव करने हेतु तथा मानकों के अतिक्रमण के विवाद में बचने के लिए, प्रत्येक शिकायत का अभिलेख रखेगा।

(ख) विधान उप विनियम (1), (2), (3), (4), (5), (6) और (7) को क्रमशः उप विनियम (3), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(ग) पुनः संख्यांकित उप विनियम (3) में आए शब्द “तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी” के स्थान पर शब्द “तो उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पदाचिन्हित किया जाए, को सूचित करेगा कि निष्पादन के मानकों का अतिक्रमण हुआ है और इन विनियमों के उपाबंध ‘क’ में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन करेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी” प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(घ) पुनः संख्यांकित उप विनियम (6) में.—

(क) विधान मद (i) के लिए निम्नलिखित मद (i) प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत :-

“(i) उप-विनियम (3) में उल्लिखित प्रतिकर का भुगतान, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर करेगा ; तथा ;” ;

(ख) विधान मद (ii) में आए शब्द, कोष्ठक और संख्या “उप-विनियम (3)” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और संख्या “उप विनियम (5)” प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ङ) यथा संशोधित पुनः संख्यांकित उप विनियम (6) के पश्चात निम्नलिखित नया उप-विनियम (6क) अन्तः स्थापित किया जाएगा ;

“(6क) उप विनियम (6) के अधीन प्रतिकर के अंसदाय से व्यथित उपभोक्ता, आयोग को, इन विनियमों के विनियम(7) की तालिका के क्रमांक (3) के अधीन, शिकायत कर सकता है” ।

4. अनुसूचित-1 का संशोधन.—उक्त विनियमों की अनुसूची-1 में—

(क) विधान मद “(2) उपभोक्ता संबन्धित सेवाएं” के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, नामत : —

(2) उपभोक्ता/सम्बन्धित सेवाएं

क	सेवा/निष्पदन के मानक की प्रकृति	सेवा देने हेतु अधिकतम समय सीमा	उद्ग्राह्य प्रतिकर		निष्पादन के मानक का लक्षित स्तर
			व्यक्तिगत उपभोक्ता को देय प्रतिकर यहाँ एक मात्र उपभोक्ता प्रभावित हो	यहाँ एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हो	
क	फयूज उड़ने/त्रुटिकाल				
	1) शहर/नगर में	6 कार्य समय घण्टे	सेवा देने हेतु अधिकतम समय सीमा से विलम्ब के लिए 10/- रुपए प्रति घण्टा	सेवा देने हेतु अधिकतम समय सीमाओं से विलम्ब के लिए 5/- रुपए प्रति घण्टा	फयूज उड़ने/त्रुटि की प्राप्त शिकायतों का 99%
	2) ग्रामीण क्षेत्र में	12 कार्य समय घण्टे			
ख	लाइन अवरोध				
	(i) शहर/नगर में	(क) जहाँ खम्बों बदला जाना अपेक्षित नहीं है 24 घण्टे	10/- स्पए प्रति चूक दिवस के लिए	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को पाँच रुपए प्रति चूक दिवस के लिए	लाइन में अवरोध की प्राप्त शिकायतों का 95%
		(ख) जहाँ खम्बों का बदला जाना अपेक्षित है 48 घण्टे	10/- स्पए प्रति चूक दिवस के लिए	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को पाँच रुपए प्रति चूक दिवस के लिए	लाइन में अवरोध की प्राप्त शिकायतों का 90%

	(ii) ग्रामीण क्षेत्र में	(क) जहाँ खम्बों का बदला जाना अपेक्षित नहीं है 24 घण्टे	10/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को पॉंच रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लाइन में अवरोध की प्राप्त शिकायतों का 90%
		(ख) जहाँ खम्बों बदला जाना अपेक्षित है 48 घण्टे	10/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को पॉंच रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लाइन में अवरोध की प्राप्त शिकायतों का 85%
(ग)	खराब वितरण ट्रान्सफार्मर का प्रतिस्थापन (Replacement)				
	(i) शहर/नगर में	एक दिन	10/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को पॉंच रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	बताए गए खराब ट्रान्सफार्मरों की संख्या का 95%
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र में	तीन दिन			
(घ)	क्षतिग्रस्त सर्विस लाईन/वायर का प्रतिस्थापन				
	(i) शहर/नगर में	एक दिन	10/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को पॉंच रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	क्षतिग्रस्त सर्विस लाईन की प्राप्त शिकायतों का 99%
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र में	दो दिन			
(ङ)	मीटरों के परीक्षण के बारे में शिकायतें				
	(i) शहरी क्षेत्रों में	शिकायत दर्ज करवाने से सात दिन में	5/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	अनुरोधों/ शिकायतों का 90%
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र में	शिकायत दर्ज करवाने से पन्द्रह दिन में			
(च)	दोषपूर्ण/बन्द/जले हुए उपभोक्ता मीटर/मीटरिंग उपकरण का प्रतिस्थापन				
	न्यून विभव (एल टी)				
	(क) शहरी क्षेत्रों में				
	(i) प्रतिस्थापन यदि उपभोक्ता का दायित्व न हो	सूचना प्राप्त होने/शिकायत दर्ज कराने की तारीख से 7 दिन में	100/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	
	(ii) जहाँ कीमत उपभोक्ता से वसूल की जानी हो या मीटर अनुज्ञप्तिधारी दिया जाना हो	मीटरिंग उपकरण का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् 7 दिन में			
ग)	ग्रामीण क्षेत्रों में				
	(i) प्रतिस्थापन यदि उपभोक्ता का दायित्व न हो	15 दिन में	100/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	90%
	(ii) जहाँ कीमत उपभोक्ता से वसूल की जानी हो या मीटर अनुज्ञप्तिधारी दिया जाना हो	मीटरिंग उपकरण का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिन में	100/- रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	90%

टिप्पणी : यदि मीटर के जल जाने से विद्युत प्रदाय प्रभावित है तो मीटर प्रस्थापन 1 दिन के अन्दर अन्दर किया जाना है। पुराने विद्युत यांत्रिक मीटरों का प्रतिस्थापन इलैक्ट्रॉनिक मीटर या पूर्व संवत मीटरों से किया जाना है।

II उच्चविभव (एचटी) उपभोक्ता					
(क)	प्रतिस्थापन यदि उपभोक्ता पर आरोपित न हो	यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास मीटर उपलब्ध है तो शिकायत प्राप्त होने के बाद 7 दिन के अन्दर अन्यथा हर हालात में 1 महीने के अन्दर अन्दर	400/-रु रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	90%
(ख)	जहाँ कीमत उपभोक्ता से वसूली की जानी हो।	यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास मीटर उपलब्ध है तो शिकायत प्राप्त/उपकरण की सुपुर्दगी के बाद 7 दिन के अन्दर अन्यथा हर हालात में 1 महीने के अन्दर अन्दर	400/-रु रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	90%
(ग)	जब मीटरिंग उपभोक्ता द्वारा दिए जाने हो	मीटरिंग उपकरणों की अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में सुपुर्दगी के बाद 7 दिन के अन्दर-अन्दर	अधिकतम 200/- रु. प्रति उपभोक्ता के अध्यक्षीन विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 200/- रु. प्रतिदिन		100%
(छ) उपभोक्ता के देयकों (Bills) सम्बन्धित शिकायतें					
	(क) शहरी क्षेत्र में	1 से 10 दिन	5 रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	प्राप्त शिकायतों का 99%	
	(ख) ग्रामीण क्षेत्र में	1 से 15 दिन			
(ज)	वोल्टेज समस्याएं				
(क)	वोल्टेज घटाव बढ़ाव				
	i) स्थानीय समस्या	4 कार्य सीमा घण्टों में	10 रूपए चूक घण्टे के लिए	5 रु. प्रति चूक घण्टे के लिए	95%
	ii) ट्रांसफार्मर टैप का बदलाव	3 दिनों में	10 रूपए चूक घण्टे के लिए	5 रु. प्रति चूक घण्टे के लिए	95%
	iii) वितरण लाइनों/ट्रांसफार्मर/कपैसिटेटर की गुरुम्मत	30 दिन में			
(ख)	न्यून वोल्टेज	30 दिन में			
(झ)	विद्युत प्रदाय का बन्द/बहाल करना				
	(क) यदि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय बन्द करना चाहता हो	हिमाचल प्रदेश विद्युत प्रदाय कोड के अनुच्छेद 7 के अनुसार	20 रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	99%
	(ख) विद्युत प्रदाय बहाल करने के लिए आवेदन की दशा में				
	उपभोक्ता संयोजन (connection) तथा सेवा परिवर्तन				
	i) स्वगित्त्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	दो मास में	10 रूपए प्रति चूक दिवस के लिए	लागू नहीं है	99%
	ii) उपभोक्ता के वैध उत्तराधिकारी नाम करना				

	iii) कान्द्रेक्ट गोंग के परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति से 30 दिन में	50 रुपए प्रति चूक के दिवस लिए	लागू नहीं है	99%
	iv) वर्ग परिवर्तन	आवेदन की स्वीकृति से 15 दिन में			
	v) न्यून दाब (LT) एकल फेज़ से न्यून दाब (LT) तीन फेज़ में ; न्यून दाब (LT) से उच्च दाब (HT) एवं विलोमत : परिवर्तन	हिमाचल प्रदेश विद्युत प्रदाय कोड के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार	50 रुपए प्रति चूक के दिवस लिए	लागू ही	99%
	vi) विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र	हिमाचल प्रदेश विद्युत प्रदाय कोड के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार	50 रुपए प्रति चूक के दिवस लिए	लागू ही	99%

अन्य मानक

(ट)	(क)नियमित परियुक्तियां करना तथा बनाये रखना	(क) उप-खण्डीय (Sub-Divisional) स्तर पर - सप्ताह में दो बार	20 / -रुपए	लागू नहीं	95%
		(ख) खण्डीय (Divisional) स्तर पर - सप्ताह में एक बार	50 / -रुपए	लागू नहीं	
		(ग) वृत्त (circle) स्तर पर पखवाड़े में एक बार	100 / - रुपए	लागू नहीं	
		(घ) मुख्य अभियन्ता स्तर पर महीने में एक बार	200 / - रुपए	लागू नहीं	

टिप्पणी :-

		(i) परियुक्तियों के दिन तथा समय बोर्ड द्वारा पूरे राज्य के सभी कार्यालयों के लिए समरूप आधार पर अधिसूचित किए जाने चाहिए। (ii) परियुक्तियों के दिन तथा समय सम्बन्धित अधिकारी के कक्ष के बाहर प्रदर्शित तथा देयक (bills) के पीछे भी मुद्रित किए जाएंगे।			
(ख)	विशेष परियुक्तियां करना तथा बनाये रखना	ऐसी परियुक्तियां उपभोक्ता के विशेष अनुरोध पर उपर्युक्त स्तरों पर बनाये रखी जा सकती हैं।	200 / - रुपए	लागू नहीं	95%
(ख)	मद (3) दक्षता-प्राचल (Efficiency Parameters) के नीचे तालिका के सतम्भ (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाएगा, नामतः -				

(ग) मद (4) विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के खण्ड (क) SAIDI तथा खण्ड (ख) SAFI में “11KV” जहां कहीं भी आया है “11KV” 15KV, 22KV तथा 33KV” प्रति स्थापित किया जाएगा।

अनुसूची II का संशोधन.—उक्त विनियमों के अनुसूची II उत्तरदायित्व केन्द्र के लिए मानक में

(क) पारिचालक निष्पादन का नीचे मद (4) के तीसरे सस्तभ में “2%” के स्थान पर “5%” प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) मीटिंग दायक प्रक्रिया तथा संग्रहण के नीचे मद (3) के तीसरे सस्तभ में “5%” के स्थान पर “2%” प्रतिस्थापित किया जाए।

6. उपाबन्ध “क” का अन्तः स्थापन.—उक्त विनियमों के अन्त में निम्नलिखित उपाबन्ध “क” जोड़ा जाएगा नामतः—

उपाबन्ध “क”

व्यक्ति उपभोक्ता द्वारा मानकीकृत प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन

1. उपभोक्ता का नाम
2. पता
3. संक्षेप में शिकायत का स्वरूप
4. तारीख व समय जब शिकायत की गई
5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शिकायत पर कारवाई की गई
6. समय सीमा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन के मानक विनियमों के अनुसार शिकायत पर कारवाई की जानी है।
7. वास्तविक समय जिसमें शिकायत पर कारवाई की गई।
8. मानकीकृत राशि, जो अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन के मानक विनियमों के अधीन प्राप्त की जानी है।

हस्ताक्षर

तारीख.....

स्थान.....

पावती (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाएगी)

दावा संख्या.....

तारीख.....

उपभोक्ता का नाम.....

दावे की राशी.....तारीख.....को वसलू की गई।

अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी के
नाम, मुद्रा तथा तारीख सहित हस्ताक्षर

आयोग के आदेश द्वारा,
हस्ता/-
सचिव।

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, 18th May, 2009

No. HPERC/Secy-401.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (za) and (zb) of sub-section (2) of section 181 read with Subsection (1) of sections 57, section 58, section 59 and clause (i) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Licensee's Standards of Performance) Regulation 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 3rd Nov., 2005, as required by the sub-section (3) of section 181 of the said Act, and the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publications in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Licensees' Standards of Performance) (Second Amendment) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of regulation-2.—In regulation 2 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Licensees' Standards of Performance) Regulations, 2005 (hereinafter called the said regulations)—

- (a) after clause 12, the following clause (13) shall be added, namely:—

“**13-“working hours”** means the working hours between 9 A.M. to 9 P.M.,” and

- (b) existing clause (13) shall be renumbered as clause (14).

3. Amendment of regulation-6.—(1) In regulation 6 of the said regulations—

- (a) at the beginning the following sub-regulations (1) and (2) shall be inserted namely:—

“(1) The licensee shall register every complaint of the consumer regarding failure of power supply, quality of power supply, meters, bill etc., at the centralized call centre or designated complaint centres, and intimate the complaint number as well as time of registration of the complaint to the consumer;

(1) the licensee shall maintain records for every complaint in order to give the fair treatment to all consumers and avoid any dispute regarding violation of standard;

- (b) the existing sub regulation (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7) shall be renumbered as sub-regulations (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) respectively.

- (c) in renumbered sub-regulation (3), after the words “as specified in Schedule-I”, the words “the consumer shall bring to the notice of the officer of the distribution licensee, as may be designated by the distribution licensee, that the Standards of Performance has been violated and shall make an application claiming compensation in the Form given in Annexure-A to the regulations, and” shall be inserted.

- (d) in the renumbered sub-regulation (6),—

- (a) for the existing item (i), the following item (i) shall be substituted namely:—

“(i) the compensation mentioned in sub-regulation (3) within thirty days of the date of receipt of application”; and

- (b) in existing item (ii) for word figure and brackets “subregulation (3) the word, figure and brackets” sub-regulation (5) shall be substituted;

- (e) after sub-regulation (6), so amended, a new sub-regulation (6-a) shall be inserted, namely:—

“(6-a) Any consumer, who is aggrieved by non-payment of compensation under sub-regulation (6) may approach the Commission under serial number 3 of the table below regulation 7 of these regulations”.

4. Amendment of Schedule-I.—(1) In Schedule –I to the said regulations.—

- (a) for existing item (2) “Consumer Related Services,” the following shall be substituted, namely:—

(2) Consumer Related Services

	Nature of Service/ Performance Standards	Maximum Time Limit for rendering service	Compensation Leviable		Targeted Level of Standard of Performance
			Compensation payable to individual consumer if the event effects a single consumer	Compensation payable to individual consumer if the event effects more than one consumer	
A	Fuse-off /Fault Calls:				
(i)	In Cities/Towns	6 working hours	Rs. 10/- for each hour of delay beyond maximum time limit	Rs. 5/- for each hour of delay beyond the maximum time limit	99% of Fuse-off/Fault complaints received
(ii)	In Rural Areas	12 working hours			
B	Line Breakdowns:				
(i)	In Cities/Towns	(a) Where replacement of pole is not required: 24 Hrs.	Rs. 10/- for each day of default	Rs. 5/- for each day of default for each consumer affected	95% of Line Breakdown complaints received
		(b) Where replacement of pole is required: 48 Hrs.	Rs. 10/- for each day of default	Rs. 5/- for each day of default for each consumer affected	90% of the line Breakdown complaints received
(ii)	In Rural Areas	(a) Where replacement of pole is not required: 24 Hrs.	Rs. 10/- for each day of default	Rs. 5/- for each day of default for each consumer affected	90% of Line Breakdown complaints received
		(b) Where replacement of pole is required: 72 Hrs.	Rs. 10/- for each day of default	Rs. 5/- for each day of default for each consumer affected	85% of Line Breakdown complaints received
C	Replacement of failed Distribution Transformer:				
(i)	In Cities/Towns	1 day	Rs. 10/- for each day of default	Rs.5/- for each day of default for each consumer affected	95% of number of transformers reported failed
(ii)	In Rural Areas	3 days			
D	Replacement of damaged service line/wire:				
(i)	In Cities/Towns	1 day	Rs. 10/- for each day of default	Rs. 5/- for each day of default for each consumer affected	99% of damaged service line complains received
(ii)	In Rural Areas	2 days			
E	Complaints about meters Testing & Checking for Correctness of Meter				
(i)	In Urban Area	7 days from lodging of complaint	Rs. 50/- each day of default	Not applicable	90% of requests/ complaints
(ii)	In Rural Area	15 days from lodging of complaint			
F	Consumers Defective/Stopped/Burnt Meter/Metering Equipment Replacement ¹ –				
(I)	LT Consumers				
(a)	Urban Area				
(i)	Replacement not attributable to consumer	7 days from the date of receiving information/ lodging of the complaint			90%

(ii)	Where the cost is recoverable from the consumer or meter is to be supplied by the licensee.	7 days after the receipt of payment of metering equipment.	Rs. 100/- for each day of default	Not applicable	
(b)	Rural Area				
(i)	Replacement not attributable to consumer	15 days	Rs. 100/- for each day of default	Not applicable	90%
(ii)	Where the cost is recoverable from the consumer or meter is to be supplied by the licensee	15 days after the receipt of payment of metering equipment.	Rs. 100/- for each day of default.	Not applicable	90%
Note:—In case of supply being affected due to burnt meters then replacement has to be to be undertaken within 1 day Replacement of old electromechanical meters may be done by Electronic Meters or Pre Paid Meters.					
(II)	H.T. Consumers				
(a)	Replacement not attributable to consumer	Within 7 days after receipt of complaint, provided meter is available with Licensee, otherwise within 1 month in any case	Rs. 400/- for each day of default.	Not applicable	99%
(b)	Where the cost is recoverable from the consumer.	Within 7 days after receipt of payment/ supply of equipment, provided meter is available with licensee, otherwise within 1 month in any case.	Rs. 400/- for each day of default.	Not applicable	100%
(c)	When the consumer is required to supply the metering equipment	7 days after delivery of metering equipment to the licensee's office			
G	Complaints about consumer's bills				
(i)	In Urban Area	1 day–10 Days	Rs. 5/- for each day of default	Not applicable	99% of complaints received
(ii)	In Rural Area	1day–15 Days			
H	Voltage problems --				
(a)	Voltage Fluctuations				
(i)	Local Problem	Within 4 working hours	Rs. 10/- for each hour of default	Rs. 5/- for each hour of default	95%
(ii)	Change of Transformer tap	Within 3 days			
(iii)	Repair of distribution Lines/ Transformer/Capacitor	Within 30 days			
(b)	Low voltage	Within 30 days			
I	Disconnection/Re-connection of supply				
(a)	onsumer wanting disconnection	As per of H.P. Electricity Supply Code	Rs. 20/- for each day of default	Not applicable	99%
(b)	Request for reconnection				
J	Transfer of consumers connection and conversion of services				
(i)	Change of consumer's name due to change in ownership/occupancy		Rs. 10/- for each day of default	Not applicable	99%
(ii)	Transfer of consumer's name to legal heir	Within two months			

(iii)	Change in contract demand	30 days after receipt of application	Rs. 50/- for each day of default	Not applicable	99%
(iv)	Change of category	Within 15 days of acceptance application			
(v)	Conversion of LT single phase to LT three phase, conversion for LT to HT and vice-versa	As per of H.P. Electricity Supply Code	Rs. 50/- for each day of default	Not applicable	99%
(vi)	Power availability certificate	As per of Draft H.P. Electricity Supply Code	Rs. 50/- for each day of default	Not applicable	99%
K	Other Standards				
(a)	Making and keeping Regular/Appointments	a) At Sub-Divisional Level -Twice a week b) At Divisional Level - Once a week c) At Circle Level - Once a fortnight d) At Chief Engineer Level -Once a month Note: i) Days and time of appointments should be notified by the Board on uniform basis for all offices throughout the State. ii) Days and time of appointment shall be displayed outside the room of the Officer concerned and also printed on the backside of the bills.	Rs. 20 Rs. 50 Rs. 100 Rs. 200	Not Applicable	95%
(b)	Making and keeping special Appointments	Such appointments may be had at the above levels at the specific request of any consumer	Rs. 200	Not Applicable	95%

(b) in item (3), "Efficiency Parameters", in the Table for columns (2) and (3) the following shall be substituted, namely:—

Parameters	Targeted level of Standard of Performance
Failure of 11/0.4, 22/0.4 and 33/04 kV Distribution Transformer.	Not exceeding 5% in a year of the number of transformers in service at the beginning of the year.
% of the stopped/defective meters	Not exceeding 2% of the meter installed

(c) in item (4), "Reliability and Quality of Power Supply", in clause (a) SAIDI and in clause (b) SAIPI for the figure and alphabet "11 kV" wherever these occur the figures and alphabets "11 kV, 15 kV, 22 kV and 33 kV" shall be substituted.

5. Amendment of Schedule-II.—In schedule II STANDARDS OF RESPONSIBILITY CENTRE of the said regulations,—

- (a) in third column of item No. 4 under heading Operational Performance i.e. for number “2%” the number “5%” shall be substituted;
- (b) in third column of item No. 3 under heading Metering, Billing and Collection for number “5%” the number “2%” shall be substituted;

6. Insertion of Annexure ‘A’.—At the end of the said regulations, the following Annexure-“A” shall be inserted, namely:—

Annexure-A
[see regulation 6(3)]

APPLICATION FOR CLAIMING COMPENSATION AMOUNT BY THE AFFECTED CONSUMER

1	Name of the Consumer	
2	Address	
3	Nature of complaint in brief	
4	Complaint Number	
5	Date and time of lodging complaint	
6	Date and time the complaint is attended to by the Licensee	
7	Standard time within which the complaint is to be attended to as per Licensees' Standards of Performance Regulations	
8	Actual Time taken to attend to the complaint	
9	Compensation amount to be received as per Licensees' Standards of Performance Regulations	

Date:

Signature

Place:

ACKNOWLEDGMENT (To be given by the Licensee)

Claim Number:

Date

Name of the Consumer

Claim for compensation amount received on (Date)

Signature of the Official of the Licensee
With Name, Seal and Date

By Order of the Commission
Sd/-
Secretary.

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

शिमला-2, 27-4-2009

अधिसूचना

संख्या पब-ए (3) 41/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब ए (3) 21/95, तारीख 10-07-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-‘अ’ का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध ‘अ’ में:—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“18 (अठारह)”।

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:—

7220-220-8100-275-10300-340-11660/ रुपए

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:—

10830/- रुपए (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर)” प्रतिमास

(ग) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“18 से 45 वर्ष”।

(घ) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जन संचार/जन सम्पर्क में स्नातक या पत्रकारिता और जन संचार/जन सम्पर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(iii) “अनिवार्य, शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी सरकारी/पब्लिक सैक्टर उपक्रम और प्रतिष्ठित समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तीन वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।”

(ङ) स्तम्भ संख्या 10 के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता”।

(च) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

- “(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।
- (ii) पचास प्रतिशत यथास्थिति, प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या भर्ती द्वारा संविदा के आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।”

(छ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सहायक लोक सम्पर्क अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो,”

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्थोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।”

- (ज) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।”
- (झ) स्तम्भ संख्या 15 के नीचे विद्यमान उपबन्ध के पश्चात् स्तम्भ संख्या 15—‘क’ अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—
“इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर नियुक्ति संविदा नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(1)संकल्पना:

(क) इस पॉलिसी के अधीन जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग रिक्त पदों को, संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) **संविदात्मक उपलब्धियाँ.**—संविदा के आधार पर नियुक्त जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, को 10830/— रु0 की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो संविदात्मक रकम में 220/— रुपये (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(iii) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.**—सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध चयन समिति/अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(v) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.**—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(vi) **करार.**—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध “ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) **निबन्धन और शर्तें.**—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 10830/— रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 220/— रुपये की दर से वार्षिक वृद्धि (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठता/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संहवदा पर नियुक्त व्यक्ति, की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक किसी भी रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त

बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित अधिकारी/कर्मचारियों पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(झ) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम संविदा पद नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा विवर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।”

(ज) स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।”

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

उपाबन्ध “ख”

जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा..... तारीख को स्वयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकमरूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष

तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी, कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यां) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. _____

 (नाम व पूरा पता)
 2. _____

 (नाम व पूरा पता)
- (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. _____

 (नाम व पूरा पता)
 2. _____

 (नाम व पूरा पता)
- (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A(3)41/99 dated 27-04-2009 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th April, 2009

No.Pub.A(3)41/99-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations District Public Relations Officer/Information Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. Pub-A (3)21/95 dated 10-07-1997, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, District Public Relations, Officer/Information Officer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—(1) In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Department of Information and Public Relations, District Public Relations Officer/Information Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997:—

- (a) For the existing provision against Column No. 2, the following shall be substituted, namely;
“18 (Eighteen)”
- (b) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely;
 - “(i) Pay scale for regular incumbents :—
Rs. 7220-220-8100-275-10300-340-11660
 - (ii) Emoluments for contract employees :—
Rs. 10830/- per month (equal to initial of the pay scale + dearness pay)
- (c) For the existing provision against Column No. 6, the following shall be substituted, namely;
“ Between 18 to 45 years”
- (d) For the existing provision against Column No. 7, the following shall be substituted, namely;
 - “(i) Bachelor Degree or its equivalent from a recognised University.
 - (ii) Bachelor of Journalism and Mass Communication/Public Relations or Post Graduate diploma in Journalism and Mass Communication/Public Relations from a recognized University.”

- (iii) Three years professional experience in Public Relations/Journalism/Mass Communication in any Government/Public Sector Undertaking and News paper/Electronics media Organization of standing gained after obtaining essential educational qualifications.”
- (e) For the existing title of Column No. 10, the following shall be substituted, namely;
- “Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.”
- (f) For the existing provision against Column No. 10, the following shall be substituted, namely;
- “(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.”
- (ii) 50 % by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.”
- (g) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely;
- “By promotion from amongst the Assistant Public Relations Officer with atleast five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal / Difficult area subject to adequate number of posts available in such area;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that the Officers / Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal /Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such area keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal / Difficult Area shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayatys of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhargal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pub Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrebar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

1. In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that :

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service /appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotions rules for the post, whichever is less,

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

(h) For the existing provision against Column No. 14, the following shall be substituted, namely—

“A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India. ”

(i) After the existing provision below Column No. 15, Column No. 15-A shall be inserted, namely;

“Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms & conditions given below:—

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—(I) Concept:

- (a) Under this policy, the District Public Relations Officer/Information Officer in the Department of Information & Public Relations H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
- (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.PSC.—The Director Information & Public Relations H.P. after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting authority i.e. H.P. Public Service Commission.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) Contractual Emoluments.—The District Public Relations Officer/Information Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 10830/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 220/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) Appointing /Disciplinary Authority.—The Secretary, Information & Public Relations H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned selection Committee/ Agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(V) Committee for Selection of contractual appointments.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.

(VI) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) Terms & Conditions.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 10830/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 220/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) for extended years and no other allied benefits such as seniority /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officer / officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provision of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

(j) For the existing provision against Column No. 17, the following shall be substituted, namely;

“Every member of the service shall pass a Departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.”

By order,
Sd/-
Secretary.

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the District Public Relations Officer/Information Officer and the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations

This agreement is made on this -----day of -----in the year -----between Sh./Smt.----- s/o/D/o Sh.-----R/o-----Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as District Public Relations Officer/Information Officer on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as a District Public Relations Officer/Information Officer for a period of 1 year commencing on day of -----and ending on the day of-----. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ----. And information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. ----- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the FIRST PARTY was engaged on contract.
4. Contractual District Public Relations Officer/Information Officer will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual District Public Relations Officer/Information Officer. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only Maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A Contractual District Public Relations Officer/Information Officer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter-part official at the minimum of payscale.
9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. _____

 (Name and full address)

2. _____

 (Name and full address)

(SIGNATURE OF THE FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. _____

 (Name and full address)

(SIGNATURE OF THE SECOND PARTY)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 23 अप्रैल, 2009

संख्या पब ए (3)19/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब-ए (3) 3/77 तारीख 30-11-1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, में तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध “अ” का संशोधन.—(1) हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, तकनीकी सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध “अ” में :—

स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

“रेडियो मकैनिक और चलचित्र चालक (प्रोजेक्टर ऑपरेटर)/ऑटो मकैनिक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाएं यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :—

(क) रेडियो मकैनिक	=	60 (साठ) प्रतिशत
(ख) चल चित्र चालक (प्रोजेक्टर ऑपरेटर)/ऑटोमकैनिक	=	40 (चालीस) प्रतिशत

चालीस प्रतिशत प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए चल चित्र चालक (प्रोजेक्टर ऑपरेटर)/ऑटोमकैनिक की युनिट-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना उनके अपने-अपने कांडर में सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी ।

प्रोन्नती के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :—

बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
1	रेडियो मकैनिक
2	रेडियो मकैनिक
3	चल चित्र चालक (प्रोजेक्टर ऑपरेटर)/ऑटोमकैनिक
4	रेडियो मकैनिक
5	रेडियो मकैनिक
6	चल चित्र चालक (प्रोजेक्टर ऑपरेटर)/ऑटोमकैनिक
7	रेडियो मकैनिक
8	रेडियो मकैनिक
9	चल चित्र चालक (प्रोजेक्टर ऑपरेटर)/ऑटोमकैनिक
10	चल चित्र चालक (प्रोजेक्टर ऑपरेटर)/ऑटोमकैनिक

रोस्टर, प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी, जिससे पद रिक्त हुआ हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्थोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव।

[Authoritative English Text of This Department Notification No. Pub-A(3)19/99 dated 23-04-2009 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th April, 2009

No. Pub-A(3)19/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Technical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide this Department notification No.Pub-(3)-3/77 dated 30-11-1996, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Technical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Information & Public Relations, Technical Assistant, (Class-III Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 :

(a) For the existing provisions against Column No. 11 the following shall be substituted, namely:

“By promotion from amongst Radio Mechanic and Project operator/Auto Mechanic who possess five years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade :—

(a) Radio Mechanic	=	60%
(b) Projector Operator / Auto Mechanic	=	40%

For the purpose of 40% promotion a combined seniority of Projector Operator and Auto Mechanic based on length of service in their respective cadre without disturbing their unitwise inter-se-seniority shall be prescribed.

For the purpose of promotion, the following 10 point roster shall be followed :—

Point No.	Category.
1.	Radio Mechanic
2.	—do—
3.	Projector Operator /Auto Mechanic
4.	Radio Mechanic
5.	—do—
6.	Projector Operator /Auto Mechanic.
7.	Radio Mechanic
8.	—do—
9.	Projector Operator /Auto Mechanic
10.	—do—

The roster will be rotated after every ten point till the representation to all the categories is achieved by given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

1. In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis, followed by regular

service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the recruitment and promotions rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.”

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult area subject to adequate number of posts available in such area;

Provided further that the proviso (I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that the Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I *supra* the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such area keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I *supra* the Tribal/Difficult Area shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pub Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrebar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

By order,
Sd/-
Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 20 मई, 2009

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(५) 232 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में सुजानपुर पटलान्दर चौरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इसस सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (म० क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (म० क्षेत्र) मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (कनाल—मरले में)
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1530 / 1	1—18
कुल किता—1				1—18

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(बी)एफ(5) 204 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव अन्द्रेटा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा में रानीताल कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (है० में)
कांगड़ा	कांगड़ा	अन्द्रेटा	100 / 1	0-02-73
			130 / 1	0-00-22
			131 / 1	0-00-24
			132 / 1	0-00-51
			133 / 1	0-00-14
			196	0-00-21
			197 / 1	0-00-13
			198 / 1	0-00-14
			199 / 1	0-00-04
			203 / 1	0-00-15
			204 / 1	0-00-32
			205 / 1	0-00-04
			243 / 1	0-00-14
			244 / 1	0-00-54
			245	0-00-13
			370 / 1	0-00-09
			561 / 1	0-00-31
			562 / 1	0-00-68
			565 / 1	0-00-73
			575 / 1	0-00-60
			577 / 1	0-01-00
			600 / 1	0-00-32
			695 / 1	0-00-72
			698 / 1	0-00-99
			700	0-02-66
			707 / 1	0-00-76
कुल किता-26			0-14-54	

शिमला-2, 19 मई, 2009

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(बी)एफ(5) 207 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पन्तेहड़, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा में रानीताल कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (है० में)
कांगड़ा	कांगड़ा	पन्तेहड़	149 / 1	0-00-75
			154 / 1	0-00-39
			157 / 1	0-00-14
			158 / 1	0-00-24
			162 / 1	0-00-69
			313 / 1	0-01-13
			311 / 1 / 1	0-03-30
			745 / 1	0-01-15
			751 / 1	0-00-18
			753 / 1	0-00-48
			754 / 1	0-00-48
			755 / 1	0-01-00
			769 / 1	0-00-52
			773 / 1	0-00-14
			774 / 1	0-00-08
			1328 / 792 / 1	0-00-26
			1329 / 792 / 1	0-00-08
			1330 / 792 / 1	0-00-08
			793 / 1	0-00-14
			797 / 1	0-00-28
			842 / 1	0-00-33
			843 / 1	0-00-18
			844 / 1	0-00-27
			945 / 1	0-00-10
			946 / 1	0-00-90
			1040 / 1	0-00-84
			1052 / 1	0-01-86
			कुल किता-27	0-15-99

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(बी)एफ(5) 201/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लंज खास, उप-तहसील हार चक्कियां, जिला कांगड़ा में रानीताल कोटला सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (है० में)
कांगड़ा	हार चक्कियां	लंज खास	183/1	0-00-14
			185/1	0-00-10
			186/1	0-00-10
			187/1	0-00-09
			215/1	0-00-20
			216/1	0-00-36
			217/1	0-00-36
			230/1	0-00-34
			246/1	0-00-12
			249/1	0-02-06
			250/1	0-00-34
			251/1	0-00-44
			252/1	0-00-15
			253	0-00-54
			563/1	0-00-05
			567/1	0-00-25
			569/1	0-00-40
			572	0-00-22
			573/1	0-00-09
			574/1	0-00-04
			608	0-00-06
			849/1	0-02-04
			850	0-00-26
			859/1/1	0-01-44
			862/1	0-00-57

864 / 1	0-00-52
865 / 1	0-00-21
866 / 1	0-00-63
867 / 1	0-01-08
920 / 1	0-00-50
1210 / 921 / 1	0-00-60
925 / 1	0-00-21
926 / 1	0-00-20
927 / 1	0-00-79
928 / 1	0-00-10
935 / 1	0-00-91
936 / 1	0-00-27
937 / 1	0-00-82
938 / 1	0-00-29
939 / 1	0-00-38
953 / 1	0-00-40
955 / 1	0-00-59
956 / 1	0-00-46
958	0-00-24
1091 / 1	0-00-12
1092 / 1	0-00-06
1094 / 1	0-00-17
1095 / 1	0-00-06
1096 / 1	0-00-05
1097 / 1	0-00-42
1143 / 1	0-01-14
1144 / 1	0-00-10
1145 / 1	0-00-92
कुल किता-53	0-23-00

शिमला-2, 19 मई, 2009

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(बी)एफ(5) 46/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नलवाड़ी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना-अग्घार-मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (है० में)
ऊना	बंगाणा	नलवाड़ी	888/43	0-12-65
			44	0-00-48
			45	0-00-24
			46	0-00-80
			47	0-06-18
			890/48	0-03-03
			60	0-07-14
			62	0-09-63
			63	0-05-57
			905/202	0-01-76
			906/202	0-36-41
			कुल किता-11	0-83-89

शिमला-2, 19 मई, 2009

संख्या पी०बी०डब्ल्यू०(बी)एफ(5) 60/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सरसकान, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्तियां दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (है० में)
मण्डी	धर्मपुर	सरसकान	141	00-07-45
			143	00-02-76
			144	00-00-45
			145	00-07-24
			147	00-01-44
			152	00-01-90
			156/2	00-06-49
			157/1	00-03-93
			157/2	00-01-52

157 / 3	00-00-14
158	00-00-98
159	00-00-54
160	00-00-65
161	00-01-22
162	00-02-46
165 / 1	00-02-18
165 / 2	00-01-17
कुल जोड़ किता-17	00-42-52

शिमला-2, 19 मई, 2009

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(बी)एफ(5) 241 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नानोवाल, तहसील नालाढ़, जिला सोलन में वागवानिया खेड़ा नैनोवाल सड़क के निर्माण करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, (द0 क्षेत्र), शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
सोलन	नालागढ़	नानोवाल	590 / 1	0-15-0
			594 / 1	0-09-0
			596 / 1	0-01-0
			596 / 2	0-04-0
			595 / 1	0-06-0
			576 / 1	0-07-0
			577 / 1	0-06-0
			567 / 1	0-14-0
			563 / 1	0-05-0
			564 / 1	0-05-0
			554 / 1	0-12-0
			552 / 1	0-03-0
			553 / 1	0-01-0
			551 / 1	0-05-0
			550 / 1	0-08-0
			544 / 1	0-01-0

547 / 1	0-12-0
336 / 1	0-01-0
337 / 1	0-02-0
335 / 1	2-11-0
332 / 1	0-01-0
331 / 1	0-00-5
358 / 1	0-03-0
360 / 1	0-09-0
279 / 1	1-02-0
711 / 1	1-11-0
267 / 1	0-03-0
714 / 1	0-01-0
724 / 1	0-01-0
725 / 1	0-06-0
730 / 1	0-02-0
189 / 1	0-17-0
कुल जोड़ किता-32	13-4-5

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव।